



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 30, 1984/माघ 10, 1905
No. 32] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 30, 1984/MAGHA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रह संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1984

का. आ. 41 (अ)/18कक/आई डी आर ए/84.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 285 (अ)/18 कक/आई डी आर ए/78, तारीख 13 अप्रैल, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के द्वारा संपूर्ण उपक्रमों अर्थात् (1) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर, (2) स्वदेशी काटन मिल्स, पांडिचेरी, (3) स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी, (4) स्वदेशी काटन मिल्स, मऊ-नाथभंजन, (5) मैसर्स उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर और (6) रायबरेली टेक्स्टाइल मिल्स, रायबरेली आफ मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त उपक्रम कहा गया है) का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन 13 अप्रैल, 1978 से 5 वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और राष्ट्रीय दस्त्र निगम लिमिटेड को संपूर्ण औद्योगिक उपक्रमों का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 283 (अ)/18 कक/आई डी आर

ए/83, तारीख 11 अप्रैल, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 31 जुलाई, 1983 तक जिसके अंतर्गत यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी ;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 525 (अ)/18 कक/आई डी आर ए/83 तारीख 27 जुलाई, 1983 के द्वारा उक्त आदेश की अवधि 31 जनवरी, 1984 तक जिसके अंतर्गत यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी ;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 30 अप्रैल, 1984 तक की और अवधि के लिए जिसके अंतर्गत यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बने रहना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 30 अप्रैल, 1984 तक की और अवधि के लिए जिसके अंतर्गत यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा ।

[फाइल सं. 3(6)/78-सी.यू.एस.]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 30th January, 1984

S.O. 41(E)/18AA/IDRA/84.—Whereas by the Order of Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 265(E)/18AA/IDRA/78 dated the 13th April, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the industrial undertakings, namely (i) Messrs Swadeshi Cotton Mills, Kanpur, (ii) Swadeshi Cotton Mills, Pondicherry, (iii) Messrs Swadeshi Cotton Mills, Naini, (iv) Messrs Swadeshi Cotton Mills, Maunath Bhanjan, (v) Messrs Udaipur Cotton Mills, Udaipur and (vi) Messrs Rae Bareilly Textile Mills, Rae Bareilly of Messrs Swadeshi Cotton Mills Company Limited, Kanpur (hereinafter referred to as the said undertakings) were taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation), Act 1951 (65 of 1951), for a period of five years from the 13th April, 1978 and the National Textile Corporation Limited was authorised to take over the management of the whole of the industrial undertakings ;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 283(E)/18AA/IDRA/83, dated the 11th April, 1983 the period of the said Order was extended upto and inclusive of the 31st July, 1983 ;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O.525(E)/18AA/IDRA/83 dated the 27th July, 1983 the period of the said Order was extended upto and inclusive of the 31st January, 1984 ;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 30th April, 1984 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 30th April, 1984.

[F. No. 3(6)/78-CUS]

का. अ. 42 (अ)/18-चख/आईडी आर ए/84.—सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)

के आदेश सं० का० आ० 277 (अ) 218 चख/आई डी आर ए/78, तारीख 28 अप्रैल, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख के ठीक पूर्व प्रकृत सभी संविदाओं, संपत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंखाओं, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी वादनाओं और दायित्वों का, (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) जिनकी निम्नलिखित रूप में ज्ञान औद्योगिक उपक्रम : (1) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर, (2) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, पांडिचरी, (3) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स नैनी, (4) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स माऊनथान, (5) मैसर्स उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर और (6) मैसर्स रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स, रायबरेली आफ मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर, एक पक्षकार हैं या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम को लागू हों, प्रवर्तन ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी वादनाएँ और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और भारत सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि लोकीहित में यह आवश्यक है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहना चाहिए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या का. अ. 209(अ)/18 चख/आई डी आर ए/79, तारीख 16 अप्रैल, 1979, का. अ. 262(अ)/18 चख/आई डी आर ए/80, तारीख 17 अप्रैल, 1980, का० आ० 305 (अ)/18 चख/आई डी आर ए/81, तारीख 20 अप्रैल, 1981, का. अ. 272 (अ)/18 चख/आई डी आर ए/82, तारीख 20 अप्रैल, 1982, का. अ. 284(अ)/18 चख/आई डी आर ए/83, तारीख 11 अप्रैल, 1983 और का. अ. 526(अ)/18 चख/आई डी आर ए/83, तारीख 27 जुलाई, 1983 द्वारा समय समय पर 31 जनवरी, 1984 तक की और अवधि तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी सम्मिलित है, ऐसे बनाए रखने के लिए घोषणा की थी ;

अतः, केन्द्रीय सरकार का असाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 30 अप्रैल, 1984 की और अवधि तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ायी जानी चाहिए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश की अवधि 30 अप्रैल, 1984 की और अवधि तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है ।

[फा० सं० 3(6)/78-सीयूएम]

ए. पी. मरखन, संयुक्त सचिव

S.O. 42(E)/18FB/IDRA/84.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Develop-

ment No. S.O. 277(E)|18FB|IDRA|78, dated the 20th April, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force, immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertakings known as: (i) Messrs Swadeshi Cotton Mills, Kanpur, (ii) Messrs Swadeshi Cotton Mills, Pondicherry, (iii) Messrs Swadeshi Cotton Mills, Naini, (iv) Messrs Swadeshi Cotton Mills, Maunath Bhanjan, (v) Messrs Udaipur Cotton Mills, Udaipur and (vi) Messrs Rae Bareilly Textile Mills, Rae Bareilly, of Messrs Swadeshi Cotton Mills Company Limited, Kanpur, are parties or which may be applicable to such industrial undertakings shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And Whereas the Central Government being of opinion that it is necessary in the interest of the general public that the said Order should continue

to have effect after the expiry of the period of one year aforesaid, had declared from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st January, 1984 vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 209(E)|18FB|IDRA|79, dated the 16th April, 1979, S. O. 262(E)|18FB|IDRA|80, dated the 17th April, 1980, S.O. 315(E)|18FB|IDRA|81, dated the 20th April, 1981, S.O. 272(E)|18FB|IDRA|82, dated the 20th April, 1982, S.O. 284(E)|18FB|IDRA|83, dated the 11th April, 1983, and S.O. 526(E)|18FB|IDRA|83, dated the 27th July, 1983 ;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of the 30th April, 1984 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 30th April, 1984.

[F. No.3(6)/78-CUS]

A. P. SARWAN, Jt Secy.

